सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 8 ● अंक: 07 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, सोमवार, 7 फरवरी, 2022
मूल्य ₹ 3/-

हर एक कामयाबी और दौलत की शुरुआत एक विचार से होती है।
-नेपोलियन हिल

बिजनौर में धूप खिल रही, भाजपा का... 8 | यूपी : एक जगह हो तो कहें दर्द... 3 | चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व तय... 2

तो भाजपा इस बेईमानी से जीतना चाहती है चुनाव

दिव्यांग से वोट डलवाने में धांधली पर हंगामा, सपा प्रमुख अखिलेश ने चुनाव आयोग को घेरा

वीडियो वायरल, मतदाता ने पोलिंग पार्टी पर लगाया जबरन भाजपा के पक्ष में वोट डालने का आरोप

» चुनाव आयोग ने रविवार से दिव्यांगों और वृद्धों को डाक पत्र के जरिए वोट डालने की शुरू की है प्रक्रिया

» सपा प्रमुख ने निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की, कार्यकर्ताओं से वोटिंग के दौरान निगरानी रखने को कहा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी विधान सभा चुनाव को लेकर प्रदेश में जहां सियासी पारा चरम पर है वहीं एक दिव्यांग ने पोलिंग पार्टी पर वोट डलवाने में धांधली का आरोप लगाया है। दिव्यांग मतदाता का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। डाक पत्र द्वारा मतदान में धांधली करने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग को घेरा है और इस मामले पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से मतदान के दौरान निगरानी रखने की अपील की है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या भाजपा इस प्रकार की धांधली से चुनाव जीतना चाहती है।

आगरा के फतेहाबाद में एक दिव्यांग मतदाता ने पोलिंग पार्टी पर गलत वोट डालने का आरोप लगाया गया। इस पर ग्रामीणों ने पोलिंग पार्टी को रोककर जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद अधिकारी गांव पहुंचे। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो में एक मतदाता आरोप लगाते हुए कह रहा है कि पोलिंग पार्टी ने उसका वोट अपने आप डाल दिया। दिव्यांग मतदाता अधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहता सुना जा रहा कि मुझे साइकिल पर वोट डालना था लेकिन इन्होंने कमल के फूल पर वोट डाल दिया। वहीं वीडियो में एसडीएम को यह कहते सुना जा रहा है कि एक वोट से कुछ नहीं होता है। गौरतलब है कि प्रदेश में पहले चरण का मतदान दस फरवरी को होना है लेकिन इस बार होने वाले विधान सभा चुनाव में चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मत पत्र की व्यवस्था की है। यह प्रक्रिया रविवार से प्रारंभ हो चुकी है। इसके तहत पोलिंग पार्टियां घर पहुंचकर डाक मतपत्र के जरिए वोट डलवा रही हैं। इस मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली के मामले में फतेहाबाद विधान सभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरूद्ध खुद ही मनमाना वोट डालने का गंभीर आरोप लगा है। चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई करे। सपा-गठबंधन के सभी समर्थक व कार्यकर्ता वोटिंग के समय पूरी निगरानी रखें। वोट डलवाने में धांधली के मामले में एक प्रशासनिक अधिकारी का सरेआम ये कहना कि एक वोट से कुछ होता है क्या बेहद गंभीर मामला है।

आज छह बजे देखिये ज्वलंत विषय पर चर्चा हमारे यू ट्यूब चैनल 4PM News Network पर

चुनाव आयोग से अपेक्षा है कि ऐसे अधिकारियों को चिन्हित कर तुरंत सस्पेंड किया जाए।

सात चरण में होने हैं चुनाव

उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए 10 फरवरी से 7 मार्च तक सात चरणों में वोट पड़ेंगे। 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। यूपी में सात चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। 10 फरवरी को पहले चरण में पश्चिम यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर, दूसरे चरण 14 फरवरी को 9 जिलों की 55 सीटों पर, 20 फरवरी को तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में मतदान 23 फरवरी को लखनऊ सहित 9 जिलों की 60 सीटों पर होगा। पांचवे चरण में 27 फरवरी को 11 जिलों की 60 सीटों पर, छठे चरण में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर और सातवें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को 9 जिलों की 54 सीटों पर किया जाएगा।

क्या है व्यवस्था

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अस्सी वर्ष से ऊपर के बुजुर्ग, दिव्यांग, कोरोना संक्रमित एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े मतदाता विधान सभा सामान्य निर्वाचन में डाक मतपत्र/पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। इसके लिए वे विधान सभा के निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित फार्म-12 डी पर डाक मत पत्र हेतु आवेदन करेंगे। विधान सभा क्षेत्र के निर्धारित कार्मिकों के द्वारा डाक मतपत्र उपलब्ध कराते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका मतदान कराया जाएगा।

विपक्ष की सरकारों ने बढ़ाए अपराध, हमने किया विकास : मोदी

» चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर बहकाने की हो रही कोशिश

» भाजपा सरकार में जाति, पंथ देखकर नहीं दिया जाता है गरीबों को पीएम आवास

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिजनौर में आयोजित रैली में नहीं पहुंच पाए लेकिन उन्होंने वर्चुअली जन चौपाल रैली को संबोधित किया और चुन-चुनकर विपक्ष पर हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी सरकारों ने प्रदेश को अंधेरे में रखा ताकि अपराध बढ़े। हमने बिजली दी ताकि विकास बढ़े। पहले की सरकारों ने यूपी का बहुत समय गंवा दिया है। पहले की सरकारों का मॉडल समस्या पैदा करो फिर सहानभुति के नाम पर सब समेट लो का था। उनके इस मॉडल से सब परेशान थे। महिलाओं से छेड़छाड़ आम बात थी। हालात इतने खराब थे कि चेन लूटे जाने पर इस बात का शुक्र मनाया जाता था कि चलो जान तो बच गई।

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में यूरिया आती थी किसानों के लिए लेकिन कालाबाजारी करने वालों के पास चली जाती थी। चौधरी चरण सिंह के आदर्शों को अपनाते हुए हर किसान का सम्मान हमारा ध्येय है। पहले की सरकारों में यूरिया और खाद के लिए यूपी के किसानों ने लाठियां तक खाई हैं। जिन्होंने सत्ता में रहते हुए किसानों को ये दिन दिखाए थे, वे किसानों का भला नहीं कर सकते हैं। ये लोग चौधरी चरण सिंह की विरासत की दुहाई देकर आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब पीएम आवास योजना में घर मिलता है तो हर गरीब को घर मिलता है। उसकी जाति, उसका पंथ, उसका क्षेत्र नहीं देखा जाता। उन्होंने कहा कि विकास का पानी नकली समाजवादियों के परिवार में उनके करीबियों में ठहरा हुआ था। ये अपने करीबियों, अपनी तिजोरियों की प्यास बुझाते रहे हैं। यही प्यास विकास की नदी के बहाव को सोख लेती है।

चुनाव के बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगा मेरी भूमिका : केशव

» भाजपा सरकार में 24 घंटे सुरक्षा की गारंटी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और भाजपा के पिछड़े वर्ग के चेहरे केशव प्रसाद मौर्य नहीं मानते कि पश्चिमी यूपी में भाजपा के स्टार प्रचारकों की भाषा में तल्खी आई है। वह कहते हैं कि कैराना पलायन और कवाल कांड को कौन भूल सकता है। उन्हें लगता है कि भाजपा फिर 300 सीट जीतकर सरकार बनाएगी। वे कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। लोगों को भाजपा पर भरोसा है। कौशांबी जिले की सिराथू सीट से नामांकन दाखिल कर चुके केशव कहते हैं कि चुनाव बाद मेरी भूमिका राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा।

उन्होंने कहा कि मेरठ में हम सभी 7 और प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट जीतने जा रहे है। यह गुंडागर्दी से मुक्ति और सुरक्षा की गारंटी का चुनाव है। भाजपा सरकार में 24 घंटे सुरक्षा की गारंटी है। पश्चिमी यूपी के लोग अपराधी, माफिया से मुक्ति पा चुके हैं, भविष्य में संकट में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए वेस्ट यूपी में भाजपा को भारी सफलता मिलने जा रही है। मैनपुरी में अखिलेश यादव की करहल समेत पांचों सीट भाजपा जीतेगी। किसानों में नाराजगी नहीं है। कृषि कानून लागू करने के बाद भी किसान नाराज नहीं थे। फिर भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानून वापस लिए, कष्ट के लिए किसानों से माफी मांगी। भाजपा सरकार ने अन्नदाता की आय बढ़ाने के लिए कदम उठाए। सपा, बसपा और कांग्रेस किसानों के जन्मजात दुश्मन हैं, वे उनके नाम पर राजनीति कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में किसानों का हर वर्ग हमारे साथ है। 2014 से उनका आशीर्वाद मिल रहा है। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य सभी तीर्थों का विकास करना है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो चुका है। कन्हैया की जन्मस्थली और उनकी लीला स्थली को भव्य स्वरूप में खड़ा करना चाहते हैं। मथुरा, वृंदावन का विकास करना चाहते हैं तो अखिलेश, प्रियंका की छाती पर सांप क्यों लोटता है। हम सभी तीर्थों का विकास करेंगे।

निशाने पर सपा-रालोद गठबंधन ही क्यों?

केशव मौर्य कहते हैं कि हमारा किसी से मुकाबला ही नहीं है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद मिलकर चुनाव लड़े थे, तब भी हमने लोकसभा की 64 सीट जीतीं, 51 फीसदी वोट लिया। सभी विरोधी एक भी हो जाएं तो भी कमल खिलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। लोगों को भाजपा पर भरोसा है। सौ में साठ हमारा, 40 में भी बंटवारा, बंटवारे में भी हमारा। हमारा मुद्दा विकास, सुशासन, कानून व्यवस्था और गरीबों का कल्याण है। किसानों की आय बढ़ाना, 24 घंटे बिजली देना, चमाचम सड़के बनाना हमारा मुद्दा है। इसके विपरीत यह कहना अतिश्योक्ति नहीं होगा कि विपक्षी दल आपराधिक गैंग को संरक्षण देते हैं।

स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई फर्क नहीं

केशव कहते हैं कि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव का स्मरण कीजिए। इन नेताओं में से कोई हमारे साथ नहीं था। प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। तब 73 सांसद जीतकर केंद्र में सरकार बनाई। किसी से आने-जाने से भाजपा पर फर्क नहीं पड़ता। ये सभी नेता अपनी सीट भी नहीं बचा पाएंगे। पिछड़ी जातियों के मतों के बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं। पूरब, पश्चिम, मध्य, बुंदेलखंड, हर जगह भाजपा की आंधी चल रही है। भाजपा के साथ अगड़ा, पिछड़ा और दलित की त्रिवेणी है। गरीब, किसान और महिलाओं के लिए जितना काम इस सरकार में हुआ, उतना पहले नहीं हुआ। भाजपा सरकार ने 4.50 लाख युवाओं को बना भेदभाव के सरकारी नौकरी दी। सपा सरकार में नौकरियो के लिए बोली लगती थी।

पूर्व मिस इंडिया पंखुड़ी के पिता से ठगी, साइबर थाने में दर्ज कराया मुकदमा

» क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज खाते से निकाले पांच लाख से अधिक

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। पूर्व मिस इंडिया पंखुड़ी गिडवानी के पिता दीपक गिडवानी से साढ़े पांच लाख से अधिक की ठगी की गई। दीपक गिडवानी ने साइबर सेल थाने में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के खाते से करीब पांच लाख 66 हजार की धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

गुलिस्ता कॉलोनी में निवासी दीपक गिडवानी के मुताबिक 2018 में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंज में खाता खोला था और 50 हजार के बिटक्वाइन खरीदे थे। जानकारी नहीं होने के कारण उन्होंने खाते से कोई लेन-देन नहीं किया। कुछ दिन पहले उन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज में खाते के दस्तावेज मिले। पता चला कि बिटक्वॉइन की कीमत पांच लाख 66 हजार हो गई है। उन्होंने जब रकम निकालने की कोशिश की तो उनका खाता ब्लाक कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कंपनी से संपर्क कर खाता चालू कराया तो पता चला कि धोखाधड़ी कर बिटक्वाइन बेच दिए गए हैं। उन्होंने गौतमपल्ली थाने में कंपनी में कार्यरत टीडी एगोस्टा, जेरेमी एलेयर, जान नेविल, जस्टिन सन और डेविड लाबर्ट तथा एक अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। क्रिप्टो करेंसी के इस तरह के कई मामले पहले भी यूपी में सामने आ चुके हैं। गौरतलब है कि दीपक गिडवानी की पुत्री पंखुड़ी गिडवानी 2016 में मिस इंडिया रह चुकी हैं।

बलिया से दयाशंकर और अमेठी से संजय सिंह को उतारा चुनाव मैदान में

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। भाजपा ने यूपी विधान सभा चुनाव के लिए 45 प्रत्याशियों की एक और सूची जारी कर दी। इसमें पांचवें, छठे व सातवें चरण के विधान सभा क्षेत्र वाले प्रत्याशी हैं। नौ विधायकों का टिकट काटा गया है। इस तरह भाजपा अब तक कुल 370 प्रत्याशी घोषित कर चुकी है जबकि गठबंधन में शामिल अपना दल एस के 13 और निषाद पार्टी के सात उम्मीद घोषित हो चुके हैं।

पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह को बलिया नगर से प्रत्याशी बनाया है। पार्टी ने मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल का

क्षेत्र बदला है। शुक्ल अब बलिया के बैरिया से चुनाव लड़ेंगे। वहां के विधायक फायर ब्रांड नेता सुरेन्द्र सिंह का टिकट काटा गया है। भाजपा के 45 प्रत्याशियों की सूची में सात महिलाए भी हैं। अमेठी से भाजपा ने संजय सिंह को उनकी पहली पत्नी व विधायक गरिमा सिंह के स्थान पर मैदान में उतारा है। संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह भी कांग्रेस के बाद भाजपा से विधायक बनी थीं। वह राम प्रकाश गुप्ता सरकार में मंत्री भी थीं। विधायक गरिमा सिंह के बदले उनके पति संजय सिंह को अमेठी से मैदान में उतारा गया है। गंभीर आरोपों में मुकदमा झेल रहे विधायक संजय प्रताप जायसवाल के बदले उनकी पत्नी संगीता प्रताप जायसवाल पर भरोसा जताया है। वाराणसी के शिवपुर से अनिल राजभर को उम्मीदवार बनाया गया है।

कोई बात गुस्से में कही जाए तो वह हिंदुत्व नहीं : भागवत

» धर्म संसद मामले में रखे अपने विचार

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। धर्म संसद के बैनर तले आयोजित कार्यक्रमों में कथित तौर पर हिंदुत्व की बातों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने असहमति जताई है। मोहन भागवत ने कहा है कि धर्म संसद से निकली बातें हिंदू और हिंदुत्व की परिभाषा के अनुसार नहीं थीं। अगर कोई बात किसी समय गुस्से में कही जाए तो वह हिंदुत्व नहीं है। मुंबई में मोहन भागवत ने कहा कि आरएसएस और हिंदुत्व में विश्वास रखने वाले लोग इस तरह की बातों पर भरोसा नहीं करते हैं। दरअसल, पिछले साल दिसंबर महीने में हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुसलमानों को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया गया था जबकि रायपुर में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की गई थी।

संघ प्रमुख ने कहा कि वीर सावरकर ने हिंदू समुदाय की एकता और उसे संगठित करने की बात कही थी

लेकिन उन्होंने यह बात भगवद गीता का संदर्भ लेते हुए कही थी, किसी को खत्म करने या नुकसान पहुंचाने के परिप्रेक्ष्य में नहीं। मोहन भागवत ने कहा यह हिंदू राष्ट्र बनाने के बारे में नहीं है। भले ही इसे कोई स्वीकार करें या न करें। यह वही (हिंदू राष्ट्र) है, हमारे संविधान की प्रकृति हिंदुत्व वाली है। यह वैसी ही है जैसी कि देश की अखंडता की भावना। राष्ट्रीय अखंडता के लिए सामाजिक समानता कदापि जरूरी नहीं है, भिन्नता का मतलब अलगाव नहीं होता। मोहन भागवत ने स्पष्ट रूप से कहा कि संघ का विश्वास लोगों को बांटने में नहीं, बल्कि उनके मतभेदों को दूर करने में है। इससे पैदा होने वाली एकता ज्यादा मजबूत होगी, यह कार्य हम हिंदुत्व के जरिए करना चाहते हैं।

पहले दो चरणों में मुस्लिम मतदाता बदल सकते हैं चुनाव परिणाम

भाजपा के लिए वेस्ट यूपी बचाना बड़ी चुनौती

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। वेस्ट यूपी में मुस्लिम मतदाता चुनाव परिणाम बदल सकते हैं। बीस जिलों में चुनावी रण सज चुका है और सियासी दल आमने-सामने हैं। पहले चरण का चुनाव दस तथा दूसरे चरण का चुनाव 14 फरवरी को है। दोनों चरणों में बड़ी संख्या में मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। अहम यह है कि कई सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद काफी है और वे चुनाव का परिणाम बदलने की कुव्वत रखते हैं।

यही कारण है कि भाजपा को छोड़ दिया जाए तो बाकी दलों ने मुस्लिमों पर खूब दांव लगाया है। शुरुआती दोनों चरणों में पश्चिमी यूपी की जिन 113 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वहां मुस्लिम वोटों की तगड़ी पकड़

है। पहले चरण में 11 जिलों की 58 और दूसरे चरण में नौ जिलों की 55 सीटों पर मतदान होना है। इन सीटों पर सपा-रालोद गठबंधन, बसपा, कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ने जमकर मुस्लिमों को टिकट दिए हैं। इन दलों ने 127 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। इनमें पहले चरण की सीटों पर 50 तो दूसरे चरण की सीटों पर 77 मुस्लिम उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। बता दें कि पहले चरण में सपा-रालोद गठबंधन के 13, बसपा के 17, कांग्रेस के 11 और एआईएमआईएम के 9 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे चरण में सपा-रालोद गठबंधन के 18, बसपा के 23, कांग्रेस के 21 और एआईएमआईएम के 15 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। पिछले चुनाव में पहले चरण वाली 58 में से 53 और दूसरे चरण वाली 55 में से 38 सीटें भाजपा ने जीती थीं। पश्चिमी यूपी की नौ सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर सब पर भारी हैं। इन नौ सीटों पर मुस्लिम वोटरों की तादाद करीब 57 फीसदी है।

यूपी : एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है!

एन के सिंह

पूर्व महासचिव, ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन

भारत में छः माह से छः साल तक 9.70 लाख बच्चे सैम (सीवियर एक्यूट मॉलन्यूट्रीशन) के शिकार हैं। इनमें करीब चार लाख उत्तर प्रदेश में और तीन लाख बिहार में हैं यानी लगभग 70 फीसदी इन दो राज्यों से। इनमें मौत की संभाव्यता सामान्य बच्चों से दस गुना ज्यादा होती है।

चुनाव है। हमारे हीं पैसों में से करोड़ों का इश्तिहार दे कर हमें ही बताया जा रहा है कि फक्र करो कि तुम योगी-काल में स्वर्ग बने यूपी में रहते हो। इसके लिए इश्तिहारी जुमला है- फर्क साफ है। हमें भोगे हुए यथार्थ को भूलने को कहा जाता है और बताया जाता है भव्य राम मंदिर बन रहा है और विकास की गंगा बह रही है। सत्ता का झूठ दो तरह से फैलाया जाता है। खैरख्वाह अधिकारी इन विज्ञापनों के जरिये अश्वत्थामा हतो जोर से बोल कर फिर धीरे से नरो वा कुंजरो कहते हैं ताकि अगर सरकार बदले तो वे कह सकें कि वे सत्य को छोड़े नहीं थे। भारत की और खासकर उत्तर भारत की और उसमें भी यूपी की अफसरशाही के पास एक वरदान है- इच्छा-शक्ति से रीढ़ को इतना लचीला बना लेने की कि केचुआ भी शर्मा जाये। दूसरा तरीका होता है कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स (सच्चाई को छुपाना)। लिहाजा इस चुनावी राज्य में आयुष्मान भारत के पिछले तीन वर्षों में हर तीन सुपात्र परिवारों में केवल एक का हीं कार्ड बन पाया जबकि राष्ट्रीय औसत हर दूसरे परिवार के कार्ड बनाने का है और बगल के कई राज्यों में 82 प्रतिशत लेकिन यह विज्ञापन में नहीं बताया जाता। यह भी नहीं कि कोरोना सरीखी महामारी में जब बेचारगी की हालत में लाशें गंगा में बहाई जा रही थीं तो इस राज्य में आयुष्मान भारत के तहत पिछले जून माह तक केवल 857 लोगों का इलाज हुआ था जबकि कर्नाटक में 1 लाख 60 हजार लोगों का और हर व्यक्ति पर औसत 50 हजार रुपये खर्च हुए थे।

नीति-आयोग की ताजा रिपोर्ट बताती है कि 43 पैरामीटर्स के आधार पर बने समग्र-स्वास्थ्य सूचकांक में फिर सबसे ऊपर केरल है जबकि सबसे नीचे यूपी जहां आज भी चिकित्सा और दवा के अभाव में नवजात और प्रसूति माताएं सबसे ज्यादा मर रही हैं? इस इंडेक्स स्कोर यूपी (31 अंक) और केरल (82 अंक) के बीच लगभग तीन गुने का अंतर क्यों पिछले चार साल से है। लेकिन चुनाव में मुख्य मुद्दे वो-बनाम-हम, मंदिर, जिन्ना, गाय, लव-जेहाद और जातिवाद है। सन 2018 में यूके और यूएस की दो यूनिवर्सिटीज ने दुनिया के 106 देशों की 100 वर्षों की स्थिति पर एक चौंकाने वाले अध्ययन में पाया कि पूर्ण वैचारिक-धार्मिक सहिष्णुता विकास की पूर्व शर्त है लेकिन योगी सरकार का भरोसा है कि करोड़ों के विज्ञापन जनता को भोगे हुए यथार्थ से विमुख कर सकेंगें।

भारत में छः माह से छः साल तक 9.70 लाख बच्चे सैम (सीवियर एक्यूट मॉलन्यूट्रीशन) के शिकार हैं। इनमें करीब चार लाख उत्तर प्रदेश में और तीन लाख बिहार में हैं यानी लगभग 70 फीसदी इन दो राज्यों से। इनमें मौत की संभाव्यता सामान्य बच्चों से दस गुना ज्यादा होती है। ये तथ्य भारत सरकार ने विगत नवम्बर में बताये और इनका कुछ अंश पिछले हफ्ते संसद में एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने बताया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत का हर तीसरा बच्चा अपनी आयु के अनुपात में नाटा होता है और उसका यह नाटापन आजीवन बना रहता है। नाटेपन की डब्लूएचओ की परिभाषा कहती है ऐसा बाधित विकास जिसका कारण कुपोषण, बार-बार बीमारी और अपर्याप्त मानसिक उत्प्रेरक। इसका परिणाम होता है बड़े होने पर बीमारी और मौत की ज्यादा गुंजाइश, सीखने की कम क्षमता, कम कार्य-स्थल पर कम उत्पादकता। इन आंकड़ों के अध्ययन में पता चला कि बेहद गरीब उप-सहारा अफ्रीका के 30 देशों के बच्चों के मुकाबले भी भारत के बच्चे ज्यादा नाटे कद के हैं।

सरकारी सत्य, अर्ध-सत्य और सफेद झूठ

चलिए, हम बेरोजगारी दर का योगी सरकार का दावा लेते हैं। सीएमआईई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि योगी ने जब बागडोर संभाली तो यह दर 2.4 प्रतिशत थी जो अब बढ़ कर 3 प्रतिशत है। वह भी इसलिए कि श्रमिकों ने रोजगार न मिलाने से गांव का रुख किया जिससे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कम हो गया लिहाजा बेरोजगारी दर घटी नजर आयी। अगर कोई रोजी की कोई गुंजायश न हो तो युवा गांव से निकलता ही नहीं है लेकिन सफेद झूठ के तहत विज्ञापन में कहा जा सकता है बेरोजगारी घटी। ऐसा मानव कल्याण/विकास का शायद ही कोई पैरामीटर हो जिस पर यूपी बेहतर प्रदर्शन कर सका हो। प्रति-व्यक्ति आय, मानव विकास सूचकांक, स्वास्थ्य इंडीकेटर्स, रोजगार और शिक्षा किसी भी समाज की बेहतरी की पहली शर्त है लेकिन मंदिर, वो-बनाम-हम के मार्कर्स और वे राम मंदिर निर्माण नहीं होने देंगें चुनाव के प्रमुख मुद्दे बनाकर सफेद झूठ का सहारा लिया जा रहा है। कभी किसानों से जा कर पूछें कि तथाकथित स्वयं भू गौ-रक्षकों की आतंक से गौवंश तो बढ़ गया लेकिन प्रदेश में किसान जब सबेरे खेत पर जा कर देखता है कि छुट्टा जानवरों ने सारी खड़ी फसल चाट ली तो उसे बेटी की शादी की चिंता होती है या पांच लाख दिए जलाये जाने की खुशी। दुष्यंत कुमार ने कहा था सर से सीने में कभी, पेट से पांवों में कभी, एक जगह हो तो कहें दर्द इधर होता है।

वे थक कर अब रोजी भी नहीं तलाशते

गालिब ने करीब सवा दो सौ साल पहले कहा था रही न ताकत-ए-गुफ्तार (बातचीत की शक्ति) और अगर हो भी तो किस उम्मीद से कहिये कि आरजू क्या है।
भारत में 15 साल से अधिक उम्र के काम के लिए तैयार किशोरों-युवाओं की कुल संख्या में काम की प्रत्याशा में खड़े लोगों के प्रतिशत को लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (एलएफपीआर) कहते हैं जो केवल 40 प्रतिशत है जबकि अन्य विकाशशील मुल्कों में यह 70 फीसदी है। इसके उलट चुनाव वाले राज्यों में हर सत्ताधारी पार्टी का दावा है कि उसके कार्यकाल में बेरोजगारी कम हुई है।

असली पैमाना है रोजगार दर न कि बेरोजगारी दर

दरअसल, सत्ताधारी दल बेरोजगारी दर घटने का हवाला देते हैं जो कि वास्तव में रोजगार चाहने वालों में रोजगार मिलने वालों का प्रतिशत है। असली राज यह है कि सन 2016 की नोटबंदी और पिछले दो वर्षों के कोरोना काल में रोजगार चाहने वालों की संख्या में और ज्यादा कमी हुई है। रोजगार चाहने वालों की कमी की वजह से बेरोजगारी का प्रतिशत कम हो जाता है जिसे ये सत्ताधारी दल अपनी कामयाबी बताते हैं। इसे समझने के लिए यूपी की स्थिति देखें। यहां पांच वर्षों में 2.20 करोड़ युवा काम की आयु के हुए लेकिन 16 लाख रोजगार काम हो गये। पंजाब में 26 लाख काम की आयु के युवा बढ़े लेकिन रोजगार कम हुए तीन लाख। यही स्थिति उत्तराखंड और गोवा की भी रही इसीलिए राजनीतिक दल या तो झूठ या अर्ध-सत्य का सहारा लेते हैं और जाति या धर्म जैसे भावनात्मक मुद्दे उठाते हैं।

सीएम योगी के प्रमुख दावों की हकीकत

4 साल 10 महीने और 14 दिन बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया। उन्होंने कुल 6 विषयों में 87 पॉइंट्स में उपलब्धियां गिनाईं। दैनिक भास्कर समाचार पत्र ने उनके दावों का एनालिसिस किया। योगी के वे 7 दावे, जिनको उनकी सरकार या किसी प्रतिष्ठित संस्थान के आंकड़े झुठलाते हैं।

1- योगी का दावा: देश की प्रतिष्ठित संस्था सीएमआईई ने जब उत्तर प्रदेश के अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तुलना की तो 2016-17 में जो 18फीसदी था आज वो 3 फीसदी है।'
सच्चाई: मार्च 2017 में जब योगी सरकार सत्ता में आई तब बेरोजगारी दर 2.4 फीसदी थी। ये आंकड़ा सीएमआईई ने ही 2017 में जारी किया था। जनवरी 2022 में 3 फीसदी है मतलब योगी के सत्ता में आने के बाद और अब में 0.6 फीसदी बेरोजगारी दर बढ़ी है

2: दावा एक भी दंगा नहीं होने का, एनसीआरबी के मुताबिक 34 दंगे हुए
योगी का दावा: बसपा सरकार के समय 364 दंगे प्रदेश के अंदर 5 वर्ष के दौरान हुए थे। सपा सरकार के समय 2012 से 2017 के बीच बड़े-बड़े दंगे 700 से अधिक हुए। सैकड़ों लोग मारे गए। प्रदेश के अंदर 2017 से अब तक कोई भी दंगा नहीं, कोई आतंकी घटना नहीं'।
सच्चाई: 11 दिसंबर 2018 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया, साल 2017 में दंगों के मामले में यूपी टॉप पर है। 2014-16 के बाद राज्य में इस तरह के सबसे ज्यादा मामले सामने आए। एनसीआरबी के आंकड़ों में 2017 में 34 सांप्रदायिक दंगे हुए और बलवों को मिलाकर 8,990 घटनाएं हुईं। साल 2019 में दंगे और बलवे शामिल करके 5,714 घटनाएं हुईं। साल 2018 में दंगे और बलवे शामिल करके 8,908 घटनाएं हुईं।

3- योगी का दावा: उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया है।
सच्चाई: 19 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ ने मनरेगा कन्वर्जेंस के अंतर्गत 18,847 सामुदायिक शौचालयों का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया। इसके बाद निर्माण भी शुरू हुए। यूपी में कुल 59,002 ग्राम पंचायत के अंतर्गत 97,941 गांव है। पंचायती निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार 25 सितंबर 2021 तक 52,811 सामुदायिक शौचालय बन चुके हैं। 48,565 महिला स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उसका रखरखाव कर रही है। करीब 7 हजार ग्राम पंचायतों में निर्माण नहीं हुए हैं। करीब 10,000 ग्राम पंचायतों में खराबी के

कारण यह शुरू नहीं हो सके हैं।

4- योगी का दावा: पांच सालों में सरकार ने 5 लाख नौजवानों को रोजगार दिया है। वो भी तब जब दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही थी, आर्थिक स्थिति खराब थी।
सच्चाई: योगी आदित्यनाथ की सरकार अलग-अलग समय पर अलग-अलग वादे करती रही है। 24 जुलाई 2021 को यूपी सरकार ने बताया कि पिछले साढ़े चार साल में 6.65 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी। फिर 17 सितंबर 2020 को पीएम मोदी के जन्मदिन पर सरकार ने विस्तृत रिपोर्ट जारी करते हुए 2 लाख 94 हजार 80 नौकरी देने का दावा किया। उस वक्त 85,629 भर्ती पेंडिंग थी। अगले छह महीने में भर्ती हुई। अप्रैल 2021 तक ये संख्या 3,79 लाख पहुंच गई। इसके बाद एक लाख नौकरी देने का वादा किया गया लेकिन कोई भर्ती पूरी नहीं हुई।

5- योगी का दावा: उत्तर प्रदेश में पिछले पांच साल के अंदर 2 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए।
सच्चाई: मुफ्त गैस कनेक्शन व गैस सिलेंडर की यह योजना प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के नाम से है। इसे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय संचालित करती है। इसके लिए केंद्र सरकार बजट जारी करती है। यूपी में उज्जवला योजना 1.0 के तहत 1.47 करोड़ लोगों को एलपीजी गैस कनेक्शन दिया गया। 25 अगस्त 2021 को उज्जवला योजना 2.0 की शुरुआत हुई। इसके तहत योगी सरकार का टारगेट 20 लाख लोगों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने का टारगेट रखा यानी कुल 1.67 करोड़ लोगों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया गया।

6- योगी का दावा: बेसिक शिक्षा परिषद के 1.40 लाख से अधिक विद्यालयों को स्मार्ट बनाया है। वहां बैठने के लिए डेस्क-बेंच, अलग टॉयलेट, पानी पीने की व्यवस्था की गई है।
सच्चाई: यूपी में प्राइमरी और अपर प्राइमरी मिलाकर कुल 1,58,839 स्कूल हैं। चार साल पहले ककके 68,603 स्कूलों में छात्र जमीन पर बैठते थे। स्थिति सुधरी, लेकिन अभी भी 40 हजार स्कूलों में छात्र जमीन पर बैठते हैं। करीब 20 हजार स्कूलों में अलग टॉयलेट नहीं है। इतने ही स्कूलों में बाउंड्रीवाल नहीं है। 2 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बताया कि यूपी में 2 लाख 17 हजार से अधिक पद खाली हैं। यह पूरे देश में बिहार के 2 लाख 75 हजार के बाद दूसरे स्थान पर है। इतनी बड़ी संख्या में शिक्षकों के पद खाली रखने पर स्कूलों को स्मार्ट बना पाना संभव नजर नहीं आता।

7- योगी का दावा: 2017 में जब हमारी सरकार आई तो हमने अपनी पहली कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ का कर्ज माफ किया।
सच्चाई: साल 2021 में सूचना के अधिकार के तहत आरटीआई एक्टिविस्ट राहुल कुमार ने यूपी कर्जमाफी की जानकारी मांगी थी। सवाल था बीते चार वर्षों में यूपी में कितने का कर्ज माफ किया गया। इसपर लिखित जवाब आया कि 2017 से वर्ष 2020 तक यूपी में 45 लाख 24 हजार 144 किसानों का कर्ज माफ हुआ है। रिपोर्ट कार्ड में बताया गया 86 लाख का आंकड़ा इस संख्या का दोगुना है।

साभार: दैनिक भास्कर

Sanjay Sharma

editor.sanjaysharma

@Editor_Sanjay

जिद... सच की

मुआवजे पर अदालत की सख्ती के मायने

कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजा देने में लापरवाही बरतने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने न केवल मृतक आश्रितों के आवेदनों को दस दिन के भीतर निपटाने का आदेश दिया है बल्कि राज्य सरकारों को फटकार भी लगायी है। कोर्ट ने राज्यों से कहा है कि कोरोना से मौत पर मुआवजा देकर राज्य कोई खैरात नहीं बांट रहे हैं। कल्याणकारी राज्य होने के नाते ऐसा करना उनका कर्तव्य है और तकनीकी खामियां निकालकर पीड़ितों को मुआवजा देने से इंकार नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकारों को कर्तव्यों की याद क्यों दिलानी पड़ रही है? पीड़ितों को मुआवजा देने में आनाकानी क्यों की जा रही है? क्या संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जमीन पर उतारना चुनी हुई सरकारों का कर्तव्य नहीं है? क्या मुआवजा राज्य सरकारें अपनी जेब से दे रही हैं? क्या लालफीताशाही अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों में भी अड़गा लगाने का काम करने लगी है? क्या कोर्ट के आदेश के बिना राज्य सरकारें जनहित के कार्यों को नहीं करना चाहती हैं?

पिछले दो साल से देश में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। देश में कोरोना की तीसरी लहर जारी है। इस अवधि में कोरोना की चपेट में आकर अब तक पांच लाख से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये वे आंकड़े हैं जो सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हैं। हजारों बच्चे अनाथ हो चुके हैं जबकि कई हजार परिवार में कमाने वाले की इस महामारी से मौत हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर ऐसे लोगों को मुआवजा देने का आदेश पिछले साल राज्य सरकारों को दिया था। इसके तहत पचास हजार रुपये प्रत्येक पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी कई राज्य सरकारें पीड़ितों को मुआवजा देने में आनाकानी कर रही है। अधिकारी आवेदनों में तकनीकी खामियां निकालकर निरस्त कर रहे हैं। लिहाजा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि राज्य सरकारों को पीड़ितों को मुआवजा देना ही होगा। तकनीकी खामियों वाली चाल नहीं चलेगी। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकारों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने का आदेश भी जारी किया है। सच यह है कि कई आदेश के बाद भी महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत कई राज्य सरकारें मुआवजा नहीं दे रही हैं। लोकतांत्रिक देश में राज्य सरकारों का अपने नागरिकों के प्रति यह रवैया उचित नहीं कहा जा सकता है। सरकारों को चाहिए कि वे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक तत्काल मुआवजा उपलब्ध कराएं।

सवाल यह है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकारों को कर्तव्यों की याद क्यों दिलानी पड़ रही है? पीड़ितों को मुआवजा देने में आनाकानी क्यों की जा रही है? क्या संविधान के कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जमीन पर उतारना चुनी हुई सरकारों का कर्तव्य नहीं है? क्या मुआवजा राज्य सरकारें अपनी जेब से दे रही हैं?

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

लोकतंत्र के शुद्धीकरण का पर्व है चुनाव

राजकुमार सिंह

चुनाव प्रक्रिया को लोकतंत्र की प्राणवायु माना जाता है। यदि प्राणवायु दूषित हो तो लोकतंत्र का स्वास्थ्य कैसा होगा? गुणवत्ता की बहस जिस तरह वायु प्रदूषण के संदर्भ में हमारे देश में अप्रासंगिक हो गयी है, उससे भी बुरा हाल लोकतंत्र की प्राणवायु यानी चुनाव प्रक्रिया का है। चुनाव प्रक्रिया की स्वच्छता कई कारकों पर निर्भर करती है लेकिन सबसे अहम है चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार। जैसे उम्मीदवार होंगे, वैसा ही प्रचार होगा, जिससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। यही उम्मीदवार निर्वाचित जन प्रतिनिधि के रूप में संसद या विधानसभाओं में पहुंच कर कानून निर्माता बनते हैं। जाहिर है, जैसे हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होंगे, वैसी ही उनकी प्राथमिकताएं होंगी और अंतत: वे वैसी सत्ता व्यवस्था भी बनायेंगे।

भारतीय राजनीति में धनबल और बाहुबल के बढ़ते प्रभाव पर अरसे से हर स्तर पर चिंता जतायी जाती रही है लेकिन समस्या के निराकरण की दिशा में ईमानदार ठोस प्रयास न किये जाने का ही परिणाम है कि दवा के दावों के बावजूद मर्ज बढ़ कर नासूर बनता दिख रहा है। धनबलियों और बाहुबलियों के प्रभाव का लाभ उठा कर अपनी राजनीति चमकाने की प्रवृत्ति हमारे राजनीतिक दलों-नेताओं में नयी नहीं है। सत्तर के दशक में पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में कुछेक धनबलियों-बाहुबलियों की राजनीतिक उपस्थिति रही, लेकिन परंपरागत राजनेताओं के लिए अपने धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करते हुए ऐसे लोगों में खुद सत्ता-सुख भोगने की ऐसी लालसा जगी कि आज राजनीति ही ऐसे लोगों के चंगुल में फंसी नजर आ रही है। विडंबना देखिए कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में आज किसी भी दल-नेता को ऐसे बाहुबलियों को चुनावी राजनीतिक लाभ के लिए गले लगाने में शर्म नहीं आती, जिन पर हत्या-बलात्कार सरीखे जघन्य अपराध दर्ज हैं। विधान सभा चुनाव वाले राज्यों में देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जिसे अक्सर देश की राजनीति को दिशा देने का श्रेय भी दिया जाता है। उसी उत्तर प्रदेश में पहले चरण में मतदान वाली 58 सीटों पर ही एक-चौथाई उम्मीदवारों के दामन पर गहरे आपराधिक दाग हैं तो ऐसी प्रदूषित प्राण वायु से कैसा और कितना स्वस्थ लोकतंत्र बनेगा—यह जानने के लिए किसी गहन शोध की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए।

चुनाव सुधार के मामले में चुनाव आयोग से लेकर राजनीतिक दलों तक की कथनी-करनी में फर्क इतना ज्यादा

है कि अब उनसे किसी तरह की उम्मीद रखना भी बेमानी लगता है। सच तो यह है कि देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा भी इस दिशा में की गयी पहल के गहरे संकेतों की गंभीरता भी राजनीतिक दल और चुनाव आयोग नहीं समझना चाहते। 10 फरवरी को पश्चिमी यूपी की जिन 58 विधान सभा सीटों पर मतदान होना है, वहीं लगभग 25 प्रतिशत उम्मीदवार ऐसे हैं, जिनके विरुद्ध गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों में से किसी ने भी ऐसे दबंगों पर चुनावी दांव लगाने से परहेज नहीं किया। चुनाव मैदान में ताल ठोंक रहे इन दबंगों ने, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के चलते, अपने इन कारनामों का खुलासा खुद नामांकन पत्र के साथ दाखिल हलफनामे में किया है। एडीआर ने जिन 615 उम्मीदवारों के हलफनामों का विश्लेषण किया है, उनमें सबसे ज्यादा दागी 75 प्रतिशत समाजवादी पार्टी के हैं जबकि उसके सहयोगी रालोद के ऐसे उम्मीदवारों का प्रतिशत 59 है। देश में नयी तरह की राजनीतिक संस्कृति विकसित करने का दावा करने वाली भाजपा ने भी 51 प्रतिशत दागियों पर दांव लगाया है तो ऐतिहासिक पराभव के दौर से गुजर रही कांग्रेस के दागी उम्मीदवारों का प्रतिशत 36 है। मायावती की बसपा के उम्मीदवारों में दागियों का प्रतिशत 34 है तो आम आदमी की राजनीति करने का दम भरने वाले केजरीवाल की आप ने भी 15 प्रतिशत अपराधियों पर दांव लगाया है। बेशक इन्हें अभी तक न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से दोषी नहीं ठहराया गया है लेकिन अगर हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार और धन शोधन-फर्जीवाड़े सरीखे गंभीर मामले लंबित हों, जिनमें सात वर्ष से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती हो तो लोकतंत्र की शुचिता के प्रति उसके स्वयंभू ठेकेदारों की प्रतिबद्धता पर गंभीर सवाल तो उठेंगे ही। सामाजिक न्याय से लेकर राष्ट्रवाद तक के इन स्वयंभू पैरोकारों के पास चुनाव लड़वाने के लिए साफ छवि वाले उम्मीदवार तक नहीं हैं, तो यह उन पर एक गंभीर सवालिया निशान है।

समावेशी विकास पर हो जोर

Oxfam

इंदिरा हिरवे

सत्ता में आने के साथ वर्तमान सरकार ने समावेशी विकास का भरोसा दिलाया था, जहां सभी वर्गों के लोग विकास प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और सबको समान रूप से फायदा होता है। ऐसा तब होता है, जब भारत जैसी गरीब अर्थव्यवस्था में आबादी के निचले 40 फीसदी हिस्से की आय में वृद्धि शीर्ष के 10 फीसदी लोगों से अधिक हो, लेकिन हालिया प्रकाशित ऑक्सफैम विषमता रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 2015 से निचली 40 फीसदी आबादी की कीमत पर शीर्ष के एक फीसदी लोगों के पास अधिक आय जाती रही है।

शीर्षस्थ एक फीसदी के पास राष्ट्रीय संपत्ति का 42.5 फीसदी है जबकि निचली 50 फीसदी आबादी के पास महज 2.8 प्रतिशत हिस्सा ही है। देश के सबसे धनी 100 अरबपतियों की संपत्ति 775 अरब डॉलर है और उनका रहन-सहन सबसे गरीब 55.50 करोड़ (आबादी का 40 फीसदी) से बिल्कुल अलग है। 2020 में 5.90 करोड़ लोग बेहद गरीब थे, जिनकी संख्या 2021 में बढ़ कर 13.40 करोड़ हो गयी जबकि अरबपतियों की संख्या में भी 40 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। स्पष्ट है कि आबादी का निचला तीस से चालीस फीसदी हिस्सा हाशिये पर है और वंचित है। उत्पादक रोजगार में बड़ा विस्तार समावेशी विकास की मूलभूत शर्तों में है लेकिन देश में महामारी से पहले ही 45 सालों की सबसे अधिक बेरोजगारी दर थी जो बीते दो सालों में और बढ़ी है। बजट में इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार, प्रधानमंत्री गति शक्ति कार्यक्रम में पूंजी खर्च बढ़ाने से आगामी पांच सालों में 60 लाख रोजगार सृजित होंगे। इससे बेरोजगारों की बड़ी संख्या कम करने में खास मदद नहीं मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर विकास ठीक है पर इससे सही रोजगार सृजन में समय लगता है। गति शक्ति कार्यक्रम में भागीदारी के लिए अपेक्षित राज्यों के पास संसाधनों और क्षमता की कमी है। ग्रामीण लोगों के लिए मनरेगा एक तरह की जीवन रेखा साबित हुई है। अब मनरेगा के आवंटन में 25 फीसदी की कटौती कर दी गयी है। इस कार्यक्रम के तहत 20 हजार करोड़ रुपये की मजदूरी बाकी है।

ऐसे में आगामी सालों में ग्रामीण रोजगार प्रभावित होगा। शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना न होने से बेरोजगारी बढ़ेगी। बजट में खाद्य अनुदान में 28 फीसदी तथा फर्टिलाइजर और पेट्रोलियम सब्सिडी में 11-11 फीसदी कमी की गयी है। ग्रामीण विकास के बजट में 0.3 प्रतिशत की कटौती हुई है, जबकि कृषि बजट में महज 2.5 फीसदी वृद्धि की गयी है। मुद्रास्फीति के मद्देनजर, बढ़त के बावजूद इस मद में कमी हो सकती है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए भी बजट में कुछ खास नहीं दिया गया है। पिछले साल अर्थव्यवस्था में कुल उपभोग खर्च में पांच फीसदी की गिरावट आयी। नगदी हस्तांतरण के अभाव और अपर्याप्त रोजगार के कारण उपभोग बढ़ने की संभावना नहीं है, खासकर मुद्रास्फीति के उच्च स्तर में, जिसका कोई स्पष्ट समाधान सरकार के पास नहीं है। आगामी सालों में मांग में कमी जारी रह सकती है, जिससे एक ओर निजी निवेश बाधित होगा तो दूसरी ओर आबादी के निचले हिस्से के लिए मुश्किलें बढ़ती रहेंगी।

स्वास्थ्य में आवंटन में मात्र एक प्रतिशत की वृद्धि की गयी है जो मुद्रास्फीति के हिसाब से ऋणात्मक हो सकता है। शिक्षा का बजट आवंटन 11 फीसदी बढ़ा है जो वास्तविक रूप से कम हो सकता है। आश्चर्य की बात है कि सरकार शिक्षा में दो साल के नुकसान के बाद स्कूली शिक्षा के लिए 200 टीवी चैनल स्थापित करना चाहती है, वह भी तब जब स्कूल धीरे-धीरे खुलने लगे हैं। यह बहुत देर से उठाया गया कदम है। सरकार आसानी से स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार सृजन, कृषि निवेश और छोटे-मझोले उद्यमों के लिए खर्च बढ़ा सकती थी। साथ ही, नगद हस्तांतरण से गरीबों के उपभोग में वृद्धि कर सकती थी। इन सबसे समावेशी विकास को बड़ी गति मिलती। यह सब धनिकों पर कर लगाकर किया जा सकता था लेकिन बजट में कराधान से संबंधित कोई बदलाव नहीं किया गया है।

अभी संपत्ति कर शून्य है, आयकर दरें भी पिछले साल के स्तर पर हैं तथा अन्य करों में भी कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। कर राजस्व में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में उछाल की वजह से है। कर और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात भारत में कम है। यह 2017-18 में 10.7 फीसदी था, जो 2020-21 में घटकर 9.9 प्रतिशत हो गया। इस जीडीपी के स्तर पर यह शायद दुनिया में सबसे कम अनुपातों में से है। इसे बढ़ाने की बड़ी संभावनाएं हैं। निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है कि आबादी के निचले 30-40 फीसदी हिस्से के लिए सरकार की प्रतिबद्धता बहुत सीमित प्रतीत होती है। सरकार का मुख्य ध्यान विभिन्न प्रकार की उचित-अनुचित सुविधाएं देकर शीर्षस्थ धनिकों और कॉरपोरेट सेक्टर को अधिक धनी बनाने पर लगा हुआ है। सरकार अभी भी सकल घरेलू उत्पादन की उच्च वृद्धि दर हासिल करने को अपना बड़ा लक्ष्य मानती है, लेकिन उसे इस विकास की संरचना की परवाह नहीं है। यह पूंजीवाद नहीं है और न ही यह बाजार के अनुकूल विकास करने की राह है। यह एक विकृत नव-उदारवादी विकास का रास्ता है, जो एक विकृत राजनीतिक आर्थिकी से पैदा होता है।

कितनी मात्रा में करना चाहिए हल्दी का सेवन

हल्दी हमारे खाने में पड़ने वाला एक आवश्यक मसाला है, जिसका इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है। हल्दी वैसे एक गुणकारी और एंटीसेप्टिक मसाला है जो पेट में जलन, गैस और ब्लोटिंग जैसी समस्या के लिए रामबाण की तरह काम करती है। हल्दी की बढ़ती लोकप्रियता के वजह से इसका इस्तेमाल खाने के अलावा लाटे, स्मूदी, शेक और कैप्सूल के तौर पर भी किया जाने लगा है लेकिन क्या आप जानते हैं कि हल्दी तभी असरदायक है जब आप इसका सेवन उचित मात्रा में करें। आइए जानते हैं, अब हल्दी के इतने विकल्पों में कौनसा विकल्प सबसे ज्यादा प्रभावी है और इसका सेवन कैसे करना ज्यादा प्रभावी होता है, लाटे, कैप्सूल या फिर एक मसाले की तरह।

करक्यूमीन की वजह से

हल्दी का लोकप्रिय होने की वजह है इसमें पाया जाना वाला कारक करक्यूमीन है। जो हल्दी में मामूली तौर पर पाया जाता है। अगर आप हल्दी से पाए जाने वाले पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए कैप्सूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको कैप्सूल में करक्यूमीन की मात्रा जरूर जांच लें। ऐसा माना जाता है पेट की जलन और गैस से बचने के लिए कम से कम 500 से 1000 मिलीग्राम करक्यूमीन की आवश्यकता होती है। एक चम्मच पीसी हुई हल्दी में करीबन 200 मिलीग्राम करक्यूमीन पाया जाता है।

अनेकों विकल्प

माना कि हल्दी की कैप्सूल या फिर गोली लेना सबसे आसान तरीका है लेकिन आप चाहें तो करक्यूमीन की पूर्ति कई अलग-अलग चीजों से भी कर सकते हैं जैसे कि खाने में मसाले की तरह कॉफी या फिर स्मूदीज में भी। सही मात्रा में हल्दी के सेवन से आपकी सेहत तो बन सकती है लेकिन इससे समस्या पूरी तरह ठीक नहीं हो सकती है।

खाने का स्वाद बढ़ाएं

करक्यूमीन बहुत ही असरदायक है लेकिन यह बहुत जल्द ही अवशोषित हो जाता है इसलिए आप इसे कितने ही सही मात्रा में सेवन कर लें लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसका सही असर होगा या नहीं इसलिए हल्दी को किसी दूसरे पावरफुल मसाले के साथ लेना चाहिए जैसे कि काली मिर्च क्योंकि हल्दी को जब कालीमिर्च के साथ लिया जाता है तो जलन से लड़ने की इसकी क्षमता बढ़ जाती है। इसी वजह से बहुत से हल्दी की कैप्सूल्स में काली मिर्च भी पाई जाती है।

धनिया न सिर्फ खाने का जायका बढ़ाता है बल्कि यह स्वास्थ्य संबंधी कई परेशानियों को दूर करने में मदद करता है। यह डायबिटीज से लेकर पाचन क्रिया को सुधारने में मदद करता है।

सेहत के लिए गुणकारी है धनिया

धनिया एक जादुई हर्ब है जोकि खाने का जायका बढ़ा देता है। भारतीय खाने में भले ही इसे जायका बढ़ाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता हो, लेकिन यह अच्छी सेहत के लिए भी बेहद जरूरी है। धनिया पत्ता ही नहीं बल्कि इसके बीज भी काफी गुणकारी हैं। क्या आप जानते हैं कि धनिया के बीज स्वास्थ्य संबंधी किन-किन परेशानियों को दूर रखते हैं।

कोलेस्ट्रॉल को करता है कम

धनिया बेड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है। धनिया में कॉपर, जिंक, आयरन और अन्य जरूरी तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं जोकि रेड ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ाने में मदद करते हैं और हार्ट को भी सुरक्षित रखता है। धनिया शरीर का मेटाबॉलिज्म भी सुधारता है।

पाचन क्रिया में करे सुधार

धनिया पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। आंत से संबंधी परेशानियों जैसे कि सूजन, गैस्ट्रिक, डायरिया और उल्टी जैसी परेशानियों को दूर करता है। यदि यह कहा जाए कि पाचन संबंधी परेशानियों के लिए धनिया रामबाण इलाज है, तो गलत नहीं होगा। धनिया में डायटरी फाइबर्स होते हैं और इनमें एंटीऑक्सिडेंट्स की भी पर्याप्त मात्रा होती है। इनकी वजह से लीवर सही तरह से अपना कार्य करता रहता है।

डायबिटीज में लाभकारी

डायबिटीज से पीड़ित लोगों के लिए भी धनिया फायदेमंद है। इसमें काफी मात्रा में एंटीऑक्सिडेंट्स और अन्य जरूरी तत्व होते हैं जोकि ब्लड शुगर को रेग्युलेट करने में मदद करते हैं। इसके अलावा धनिया वजन घटाने और मोटापा कम करने में भी मदद करता है।

बालों और स्किन के लिए फायदेमंद

धनिया में विटामिन के, सी, बी और अन्य मिनरल्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जोकि स्किन और बालों के लिए काफी गुणकारी हैं। अगर आप रोजाना अपनी डायट में धनिया शामिल करते हैं तो ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पा सकते हैं।

हंसना मना है

चंगू अपनी बीवी से: मैं तुमसे तंग आ चुका हूं। बीवी: क्यों ? मैंने क्या किया? चंगू: भगवान के लिए चुप हो जाओ, मुझे अब 'शांति' के साथ रहना है। बीवी: हां-हां मुझे भी नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे भी 'अमन' के साथ रहना है।

पुलिस: हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, सुना है आपके घर में विस्फोटक सामग्री है! सोनू: खबर तो पक्की है पर अभी वो अपने मायके गई है।

पप्पू: पंजाब एक्सप्रेस कब आएगी? टीटी: पांच बजे। पप्पू: लोकल कब आएगी? टीटी: 9 बजे पप्पू: शताब्दी एक्सप्रेस कब आएगी? टीटी: 10 बजे। पप्पू: अच्छा डबल डेकर कब आएगी? टीटी: अरे भाई तुम्हें जाना कहां है? पप्पू: कहीं नहीं, बस पटरी पर सेल्फी लेनी है..!

ग्राहक: शर्ट दिखाओ। दुकानदार: ये लीजिए पीटर इंग्लैंड का शानदार शर्ट है। ग्राहक: कितने का है? दुकानदार: मात्र 4000 का। ग्राहक: तो आपके पास पीटर भोपाल, पीटर उज्जैन या पीटर खरगोन का शर्ट नहीं है!

दो दोस्त, पेपर के बाद: यार मुझे कुछ नहीं आता था, मैं पेपर खाली छोड़ आया। दूसरा बोला: मैंने भी। तीसरा बोला: अब तो गए तुम लोग काम से। पहला: क्यों। तीसरा बोला: नकल करने के आरोप में दोनों पर केस चलेगा।

कहानी — बंदर का हृदय

किसी नदी के तट पर एक वन था। उस वन में एक बंदर निवास करता था जो वन के फल आदि खा कर अपना निर्वाह करता था। नदी में एक टापू भी था और टापू और तट के बीच में एक बड़ी सी चट्टान भी थी। जब कभी बंदर को टापू के फल खाने की इच्छा होती वह उस चट्टान से उस टापू पर पहुंच जाता और जी भर अपने मनचाहे फलों का आनंद उठाता। उसी नदी में घड़ियाल की एक जोड़ी भी रहती थी। जब भी वह उस हृष्ट-पुष्ट बंदर को मीठे-रसीले फलों का आनंद उठाते देखती तो उसके मन में उस बंदर के हृदय को खाने की तीव्र इच्छा उठती। एक दिन उसने नर घड़ियाल से कहा, प्रिय ! अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मुझे उसका हृदय खिलाकर दिखा दो। नर घड़ियाल ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन बंदर जैसे ही टापू पर पहुंचा नर-घड़ियाल टापू और तट के बीच के चट्टान के निचले हिस्से पर चिपक गया। बंदर एक बुद्धिमान प्राणी था । शाम के समय जब वह लौटने लगा और तट और टापू के बीच के चट्टान को देखा तो उसे चट्टान की आकृति में कुछ परिवर्तन दिखाई पड़ा । उसने तत्काल समझ लिया कि जरुर कुछ गड़बड़ है । तथ्य का पता लगाने के लिए उसने चट्टान को नमस्कार करते हुए कहा, हे चट्टान मित्र ! आज तुम शांत कैसे हो ? मेरा अभिवादन भी स्वीकार नहीं कर रही हो ? घड़ियाल ने समझा, शायद चट्टान और बंदर हमेशा बात करते रहते हैं इसलिए उसने स्वर बदल कर बंदर के नमस्कार का प्रत्युत्तर दे डाला । बंदर की आशंका सत्य निकली । बंदर टापू में ही रुक तो सकता था मगर टापू में उसके निर्वाह के लिए पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं था। जीविका के लिए उसका वापस वन लौटना अनिवार्य था। अत: अपनी परेशानी का निदान ढूंढते हुए उसने घड़ियाल से कहा, मित्र! चट्टान तो कभी बातें नहीं करती ! तुम कौन हो और क्या चाहते हो? दम्भी घड़ियाल तब उसके सामने प्रकट हो कहा, ओ बंदर ! मैं एक घड़ियाल हूं और तुम्हारा हृदय अपनी पत्नी को खिलाना चाहता हूं । तभी बंदर को एक युक्ति सूझी । उसने कहा, हे घड़ियाल ! बस इतनी सी बात है तो तुम तत्काल अपनी मुख खोल दो, मैं सहर्ष ही अपने नश्वर शरीर को तुम्हें अर्पित करता हूं। बंदर ने ऐसा इसलिए कहा कि वह जानता था कि जब घड़ियाल मुख खोलते हैं तो उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर जैसे ही घड़ियाल ने अपना मुख खोला, बंदर ने तेजी से एक छलांग उसके सिर पर मारी और दूसरी छलांग में नदी के तट पर जा पहुंचा। इस प्रकार अपनी सूझ-बूझ और बुद्धिमानी से बंदर ने अपने प्राण बचा लिए ।

6 अंतर खोजें

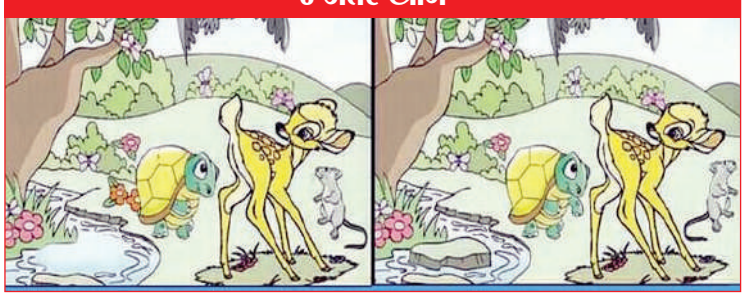

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष — प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उत्साहवर्धक सूचना मिलेगी। जोखिम व जमानत के कार्य टालें। मित्र व संबंधी मिलेंगे।

वृषभ — प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यसिद्धि होगी। प्रतिद्वंद्वी शांत रहेंगे। पराक्रम बढ़ेगा। व्यवसाय ठीक चलेगा। प्रमाद न करें।

मिथुन — झंझटों में न पड़ें। बुरी सूचना मिल सकती है। जोखिम न उठाएं। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा।

कर्क — स्वादिष्ट भोजन का आनंद मिलेगा। रचनात्मक कार्य सफल रहेंगे। धन प्राप्ति सुगम होगी। चिंता रहेगी।

सिंह — विवाद से बचें। संपत्ति के कार्य लाभ देंगे। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दूसरों के झगड़ों में न पड़ें।

कन्या — प्रेम-प्रसंग में अनुकूलता रहेगी। यात्रा मनोरंजक रहेगी। धनलाभ सुगम होगा। प्रसन्नता रहेगी।

तुला — वाहन व मशीनरी के प्रयोग में सावधानी रखें। विवाद में न पड़ें। कीमती वस्तुएं संभालकर रखें। धैर्य रखें।

वृश्चिक — कानूनी अड़चन दूर होगी। तीर्थ दर्शन हो सकता है। बेचैनी रहेगी। व्यवसाय ठीक चलेगा।

धनु — योजना फलीभूत होगी। कार्यस्थल पर परिवर्तन होगा। लाभ के अवसर बढ़ेंगे। यात्रा सफल रहेगी।

मकर — बकाया वसूली के प्रयास सफल रहेंगे। यात्रा मनोरंजक रहेगी। उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे।

कुम्भ — स्वास्थ्य कमजोर रहेगा। लेन-देन में सावधानी रखें। फालतू खर्च होगा। कुसंगति से हानि होगी।

मीन — यात्रा, निवेश व नौकरी मनोनुकूल लाभ देंगे। बेरोजगारी दूर होगी। भेंट व उपहार की प्राप्ति होगी।

साउथ | मन की बात

निक्की तंबोली की इन तस्वीरों ने मचाई सनसनी

साउथ फिल्म इंडस्ट्री से अपने करियर की शुरुआत करने वाली एक्ट्रेस निक्की तंबोली आज किसी पहचान की मोहताज नहीं रह गई हैं। बिग बॉस 14 का हिस्सा बनने के बाद उन्हें घर-घर में पहचान हासिल हो चुकी है। इस रियलिटी शो से बाहर आने के बाद कोई टीवी सीरियल या फिल्मों में काम न मिला हो, लेकिन निक्की ने अपने स्टाइलिश लुक से हमेशा ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। अब फिर से निक्की का लुक चर्चा में है। एक्ट्रेस ने फिर से अपने लेटेस्ट फोटोशूट की झलक दिखाई है। हाल ही में निक्की ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिसमें वह काफी ग्लैमरस दिख रही हैं। इनमें उन्हें फुल स्लीव्स की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहने देखा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद निक्की की बोल्डनेस देख लोगों के होश उड़ गए हैं। अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए निक्की ने न्यूड मेकअप किया है और बालों को सॉफ्ट कर्ल के साथ खुला छोड़ा है। इस लुक में निक्की काफी ग्लैमरस दिख रही हैं। उनका ये लुक अब फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। निक्की ने एक साथ अपनी बहुत सारी तस्वीरें शेयर की हैं, जहां हर एक फोटो में वह अलग-अलग पोज देती नजर आ रही हैं। अब कुछ घंटों में ही निक्की की इन फोटोज पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स आ चुके हैं।

फिल्मों में फ्लॉप करियर के बावजूद पिता पत्नी से दस कदम आगे हैं अभिषेक

अभिषेक बच्चन ने साल 2000 में फिल्म रिफ्यूजी से बॉलीवुड में कदम रखा था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई थी। हालांकि अपने करियर में अभिषेक बच्चन ने कई हिट फिल्में भी दी हैं लेकिन उनकी पहचान अमिताभ के बेटे और उसके बाद ऐश्वर्या के पति की ज्यादा रही है।

अभिषेक बच्चन जब बॉस्टन में स्नातक की पढ़ाई कर रहे थे तब अमिताभ बच्चन एबीसीएल चला रहे थे। एबीसीएल उस दौरान घाटे में चल रहा था इसलिए अपने पिता को सपोर्ट करने के लिए अभिषेक सबकुछ छोड़कर मुंबई आ गए। अभिषेक ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में प्रोडक्शन ब्वॉय का काम किया। करियर की शुरुआत में अभिषेक की कई फिल्में फ्लॉप हो गई थीं। यहां एक हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने फिल्में ना मिलने पर LIC एजेंट के काम में भी अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश की थी।

अभिषेक के फिल्मी करियर में बहुत उतार-चढ़ाव आए। उनकी ज्यादातर फिल्में फ्लॉप रहीं। हालांकि साल 2004 में अभिषेक बच्चन ने फिल्म धूम में काम किया और यह फिल्म सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म के बाद उन्होंने बंटी और बबली, युवा, ब्लफमास्टर, गुरु और दोस्ताना जैसी सुपरहिट फिल्में देकर ये साबित कर दिया कि वो बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। अभिषेक ने कहा था, जब कोई एक्टर फ्लॉप फिल्में देता है तो लोग उसका फोन उठाना बंद कर देते हैं। फिर वो यह नहीं सोचते कि आप किसके बेटे या बेटी हो। फ्लॉप होना दुनिया की सबसे खराब फीलिंग होती है जो आपको एक इंसान के तौर पर खत्म सा कर देती है। अभिषेक को कई बार खराब एक्टिंग के लिए ट्रोल भी किया जा चुका है। उनकी तुलना हमेशा उनके पिता से होती रही है। हालांकि, अभिषेक बच्चन एक एक्टर से ज्यादा कहीं अच्छे बिजनेसमैन हैं। वे दो सफल स्पोर्ट्स टीम प्रो कबड्डी टीम और जयपुर पिंक पैंथर्स के मालिक हैं। इसके अलावा वह इंडियन सुपर फुटबॉल लीग में चेन्नईयिन फैन क्लब के भी मालिक हैं। ये टीम दो बार इंडियन सुपर फुटबॉल लीग का खिताब जीत चुकी है। अभिषेक बच्चन एक्टर के अलावा एक सफल प्रोड्यूसर भी हैं। वह अपने पिता की कंपनी ए.बी.कॉर्प लिमिटेड का भी कामकाज देखते हैं। वह एलजी होम अप्लायंसेज, अमेरिकन एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड, वीडियोकॉन डीटीएच, मोटोरोला मोबाइल, फोर्ड कार, आइडिया मोबाइल, ओमेगा वॉच और टीटीके प्रेस्टीज जैसी कंपनियों का विज्ञापन करते हैं। उन्हें निवेश करने के लिए भी जाना जाता है।

बॉलीवुड | मसाला

सुनील ग्रोवर की सेहत को लेकर फिक्रमंद हुए सलमान

एक्टर और कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हाल ही में हेल्थ कारणों से चर्चाओं में आए हैं। सुनील की हार्ट सर्जरी हुई है और अब वे पहले से काफी बेहतर हैं। यह सर्जरी मुंबई के एशियन हार्ट इंस्टिट्यूट में हुई थी। बताया जा रहा है कि पिछले महीने ही सुनील को सीने में दर्द हुआ था जिसके बाद से ही वे डॉक्टरों की निगरानी में लगातार बने हुए थे।

बहरहाल, अब खबर ये है कि सलमान खान खुद सुनील ग्रोवर की हेल्थ को लेकर फिक्रमंद हैं और उन्होंने अपने डॉक्टरों की टीम से कॉमेडियन की हेल्थ पर नजर रखने के लिए कहा है। आपको बता दें कि सलमान खान और सुनील ग्रोवर फिल्म 'भारत' में साथ काम कर चुके हैं। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सुनील ग्रोवर का नाम सलमान खान के करीबियों में आता है। सलमान खान के डॉक्टरों की एक टीम, एक्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट 'बींइग ह्यूमन' के साथ काम करती है। सलमान ने अपने डॉक्टरों की टीम से कहा है कि वे सुनील ग्रोवर की हेल्थ पर बारीक से नजर रखें और यह सुनिश्चित करें कि कॉमेडियन ठीक हैं।

सलमान के अलावा कॉमेडियन कपिल शर्मा भी सुनील की हेल्थ को लेकर फिक्रमंद हैं। कपिल की मानें तो उन्हें यह जानकर शॉक लगा था कि सुनील की हार्ट सर्जरी हुई है। कपिल कहते हैं कि, 'सुनील की सर्जरी की बात सुनकर मैं पूरी तरह से शॉक्ड था, मैं उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद हूं। मैंने उन्हें मैसेज भी किया था हालांकि, वे कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वे मैसेज का जवाब दे पाएंगे'।

बॉलीवुड | गपशप

अजब-गजब | आज भी इसमें जाने के नाम से कांपने लगते हैं लोग

काला जादू करने वाले तांत्रिक के शाप से श्रापित हो गया था ये किला

हमारे देश में प्राचीन काल के तमाम किला और महल आज भी मौजूद हैं। इनमें से कुछ किलों को अब भूतिया माना जाता है। इसीलिए इन किलों में लोगों के जाने की हिम्मत नहीं होती। राजस्थान में भी ऐसे कई किले मौजूद हैं जो भूतिया हैं। ये किले सदियों से वीरान पड़े हुए हैं ऐसा माना जाता है कि इन किलों में अब भूत प्रेत रहते हैं इसीलिए लोग यहां जाने के नाम से ही घबराते हैं। ऐसे ही एक किले के बारे में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। यह किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। जिसे भानगढ़ का किला नाम से जाना जाता है।

इस किले को भी भूतिया किला माना जाता है। इस किले को खौफ का आलम ये है कि यहां कोई आस-पास भी आने से डरता है। इस किले में प्रवेश वर्जित है। इस किले के भूतिया होने के पीछे की कहानियां है। बता दें कि भानगढ़ किले का निर्माण आमेर के कछवाहा शासक राजा भगवंत सिंह ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए 1573 ई। में करवाया था। माधो सिंह के भाई प्रसिद्ध मान सिंह थे, जो अकबर के सेनापति थे। माधो सिंह का उत्तराधिकारी उसका पुत्र छत्र सिंह था। छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह ने अजबगढ़ का किला बनवाया था। फिलहाल यहां दूर-दूर से पर्यटक घूमने आते हैं। जिन्हें वहां के गाइड कहानी सुनाकर बताते हैं कि आखिर ये किला कैसे भूतिया बन गया। बताया जाता है कि किले में राजकुमारी रत्नावती रहती थी जो बहुत ही सुंदर थीं। राजकुमारी रत्नावती छत्र सिंह की बेटी थी। रत्नावती अपने सौतेले भाई अजब सिंह से बहुत छोटी थी। राजकुमारी की सुंदरता और अच्छे स्वभाव के किस्से दूर-दूर तक फैले। जिससे राजकुमारी को शादी के कई प्रस्ताव मिले। इस बीच काला जादू करने वाले एक तांत्रिक को राजकुमारी से प्यार हो गया। कहा जाता है कि तांत्रिक जानता था कि राजकुमार उसे नहीं मिलेगी। बावजूद इसके वो उसके पीछे पड़ गया। एक दिन राजकुमारी अपनी दासी के साथ गांव में इत्र खरीदने गई थी। ये देख तांत्रिक ने उस पर जादू कर दिया, जिससे रत्नावती को उससे प्यार हो जाए। रत्नावती को इस बात का पता चला और उन्होंने बोतल फेंक दी। बोतल टूट के बाद कुछ अजीब और बड़ी चीज निकली और तांत्रिक से टकरा गई। तांत्रिक उसके नीचे दब गया, लेकिन मरने से पहले उसने राजकुमारी, उसके परिवार और पूरे गांव को श्राप दे दिया।

इस आइलैंड पर इंसान नहीं बल्कि खरगोश रहते हैं

आपने दुनियाभर में तमाम रहस्मयी द्वीपों के बारे में सुना और पड़ा होगा। जहां कुछ रहस्यमयी घटनाएं हो जाती होंगी या वहां इंसानों के जाने पर रोक लगी हो। आज हम आपको एक ऐसे ही द्वीप के बारे में बताने जा रहे है जहां इंसान नहीं बल्कि खरगोश रहते हैं इसीलिए इस द्वीप को खरगोशों का द्वीप कहा जाता है। दरअसल हम बात कर रहे हैं जापान के ओकुनोशिमा हिरोशिमा प्रीफेक्चर के टेकहारा में स्थित एक छोटे से द्वीप के बारे में। इस द्वीप में रहने वाले कई जंगली खरगोशों के कारण इस द्वीप को उसगी जिमा यानी खरगोश द्वीप के रूप में भी जाना जाता है। इस द्वीप को पर्यटन के लिए एक आदर्श स्थान माना जाता है। बता दें कि इस द्वीप को शुरू में युद्ध के लिए गैसों के घातक विकास के उद्देश्य से बनाया गया था और जहां 6 हजार टन से अधिक का घातक गैसों का उत्पादन किया गया था, लेकिन युद्ध के अंत के साथ, इस पूरी परियोजना को छोड़ दिया गया और गुप्त रखा गया, इसलिए द्वीप पूरी तरह से निर्जन और अज्ञात था। बता दें कि इस द्वीप पर अब आपको कई रेस्टोरेंट और होटल भी मिल जाएंगे लेकिन यहां सबसे ज्यादा आबादी खरगोशों की है। बता दें कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस द्वीप को छोड़ दिया गया, तो रासायनिक हथियारों की प्रभावशीलता का परीक्षण करने के लिए उपयोग किए जाने वाले खरगोशों को यहां छोड़ दिया गया। हालांकि, सरकार के अनुसार, उन्हें कारखानों के साथ नष्ट कर दिया गया था, उनका दावा है कि द्वीप पर मौजूद मौजूदा खरगोशों का परीक्षणों में इस्तेमाल किए गए खरगोशों से कोई लेना-देना नहीं है। हालांकि उनमें से कुछ के बचे रहने की भी बात कही जाती है। बता दें कि इस द्वीप पर पाए जाने वाले खरगोशों के शिकार करने पर पाबंदी लगी हुई है। साथ ही इस द्वीप पर बिल्लियों और कुत्तों को भी ले जाने पर पाबंदी है। बता दें कि इस द्वीप में 1988 में एक संग्रहालय भी खोला गया है ताकि अधिक से अधिक लोगों को जहरीली गैस के बारे में भयानक सच्चाई दिखाई जा सके।

समाजवादी पार्टी का संकल्प

समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर घरेलू उपभोक्ताओं को

300 यूनिट फ्री बिजली

/samajwadiparty

www.:// samajwadiparty.in

अधिक जानकारी के लिए
कृपया लॉग इन करें
www.samajwadiparty.in

निवेदक: पुष्पक ढिल्लों
Mob: 9927330303 @Pushpakdhillo

कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी
40 नौगावां सादात (अमरोहा)

ब्राह्मणों की हत्या को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले लंभुआ विधायक देवमणि का बीजेपी ने काट दिया टिकट

विधानसभा में अपनी ही सरकार से पूछा था सवाल कि ब्राह्मणों पर इतना अत्याचार क्यों

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

सुल्तानपुर। विधानसभा में ब्राह्मणों की हत्या को लेकर योगी सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले लंभुआ विधायक देवमणि का बीजेपी ने टिकट काट दिया है। जबकि पिछली बार वह रिकॉर्ड मतों से जीते थे। भाजपा ने कल देर रात 45 सीटों पर टिकट फाइनल किए और इस सूची में सुल्तानपुर से दो विधायकों का टिकट काट दिया गया। उसमें एक नाम सुल्तानपुर के विधायक सूर्यभान सिंह तो दूसरा नाम लंभुआ विधायक देवमणि द्विवेदी का है। ऐसे में चर्चाओं का बाजार गर्म है कि डेढ़ साल पहले विधायक ने अपनी ही सरकार से सदन में सवाल कर लिया था कि तीन साल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई? कहीं यह तो नहीं टिकट कटने का मूल कारण बन गया।

16 अगस्त 2020 को विधायक देवमणि द्विवेदी ने विधानसभा के सत्र से पहले प्रदेश ब्राह्मणों के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर योगी सरकार से सवाल किया था। देवमणि द्विवेदी ने इसे लेकर विधानसभा सचिवालय को नोटिस दिया था और आगामी सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सदन में इस पर जवाब देने की मांग की थी। विधानसभा सचिवालय को भेजे गए अल्पकालिक सवाल की सूची में देवमणि द्विवेदी ने सरकार के गृह विभाग से सवाल पूछा था कि प्रदेश में बीते तीन सालों में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है। ब्राह्मणों की सुरक्षा के लिए पुलिस की नीति क्या है। सरकार के पास कितने ब्राह्मण लोगों ने लाइसेंस के लिए आवेदन किया और कितने ब्राह्मणों को शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया है, इसके आंकड़े भी मांगे गए थे। इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा कि तीन साल की अवधि में कितने अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और कितने अपराधियों को पुलिस सजा दिलाने में सफल हुई है। बता दें कि इस बार बीजेपी ने देवमणि के स्थान पर सदर विधायक सीताराम वर्मा को टिकट दिया है उनके सामने सपा के टिकट पर पूर्व विधायक संतोष पांडे हैं।

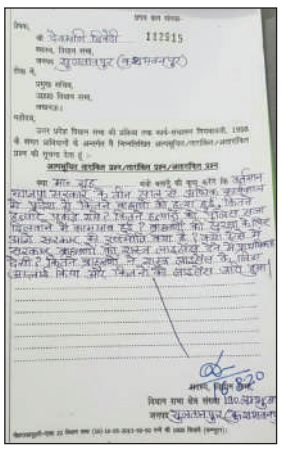

2017 में रिकॉर्ड मतों से जीते थे

आजादी के बाद 2017 में पहला मौका था जब इस सीट पर किसी प्रत्याशी को 78,627 वोट मिला था। वर्ष 1996 में भाजपा प्रत्याशी अरुण प्रताप सिंह ने 45421 मत पाकर जीत हासिल की। उसके बाद से भाजपा की हालत यहां दिन प्रतिदिन खराब होती गयी। स्थिति यह हुई कि वर्ष 2002, 2007 और 2012 के चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को दूसरा स्थान भी नसीब नहीं हुआ पर 2017 में भाजपा ने इस सीट से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। वर्ष 2012 में सपा प्रत्याशी संतोष पांडेय को 74,352 मत मिले थे।

टिकट कटा तो क्या हुआ लड़ूंगा चुनाव

देर रात भाजपा की ओर से टिकट के निर्णय के बाद बलिया जिले में भाजपा कार्यकर्ता दो फाड़ हो गए हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने बैरिया में सीटिंग विधायक सुरेंद्र सिंह का टिकट काट दिया है। यहां से मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल को टिकट दिया है। इधर विधायक सुरेंद्र सिंह ने भी चुनाव लड़ने का एलान कर दिया है। 2017 के चुनाव में भाजपा के सुरेंद्र सिंह को 64868 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर सपा के जयप्रकाश अंचल को 47791 और बसपा के जवाहर को 27974 वोट मिले थे।

बिजनौर में धूप खिल रही, भाजपा का मौसम खराब: जयंत चौधरी

» पीएम मोदी का बिजनौर आगमन रद होने पर रालोद मुखिया ने ली चुटकी

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिजनौर आगमन का कार्यक्रम रद होने पर विपक्षी दल को तंज कसने का मौका मिल गया है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 33 प्रत्याशी उतारने वाली राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी ने पीएम मोदी के बिजनौर आगमन का कार्यक्रम रद होने पर ट्वीट किया है।

प्रधानमंत्री मोदी का आज बिजनौर आगमन प्रस्तावित था। वहां पर खराब मौसम का हवाला देकर उनके आगमन के कार्यक्रम को रद कर दिया गया। पीएम मोदी के बिजनौर आगमन का कार्यक्रम रद होते ही विपक्षी दलों को मौका मिल गया। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष पूर्व सांसद जयंत चौधरी ने पीएम के कायक्रम को रद होने को लेकर एक ट्वीट किया है। मौसम विभाग के अनुमान की स्क्रीन शाट के साथ जयंत चौधरी ने लिखा है कि बिजनौर में धूप खिल रही है। बिजनौर में तो धूप है, लेकिन भाजपा का मौसम खराब है। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी ने बिजनौर का दौरा रद किया है। कहा ये भी जा रहा है कि मोदी की होनी वाली सभा में भीड़ नहीं थी। इस वजह से भाजपा ने कार्यक्रम रद्द करवा दिया। हकीकत यह है कि बिजनौर ही नहीं, वेस्ट यूपी में बीजेपी की हालत खराब है इसलिए भाजपाई बहाना बना रहे हैं।

पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर तीन लोगों की जिंदा जलकर मौत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर गोसाईगंज थाना अंतर्गत अरवल कीरी गांव स्थित एयर स्ट्रिप पर कल देर शाम हुए सड़क हादसे में कार सवार तीन लोग जिंदा जलकर राख हो गए। मरने वाले तीनों लोग लखनऊ के रहने वाले हैं।

कार का नंबर यूपी 32 केबी 7401 है। 16 नवम्बर 2021 को पीएम मोदी के लोकार्पण समारोह के बाद अब तक 85 हादसे एक्सप्रेस वे पर हो चुके हैं, जिसमें 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि लखनऊ के कपूरथला के एक बुक सेलर अपने स्टॉफ के घर आयोजित शादी में शामिल होने सुल्तानपुर आ रहे थे। उनके साथ उनकी शॉप के दो स्टॉफ भी कार पर सवार थे। मृतक बुक सेलर की शिनाख्त लखनऊ के जानकीपुरम निवासी आदित्य कोठारी के रुप में हुई है। मृतक के भाई अनिल प्रकाश कोठारी ने बताया भाई की कपूरथला में मॉर्डन बुक सेंटर के नाम से शॉप थी। उनका एक स्टॉफ सुल्तानपुर में रहता था। रविवार रात वो उसी के घर शादी में जा रहे थे। स्टॉफ में एक विक्रम और दूसरा पंकज कश्यप कार पर भाई के साथ सवार थे। सभी की जलकर मौत हुई है। अनिल ने बताया कि भाई के पीछे पत्नी प्रतिभा कोठारी और एक बेटी है। मृतक चार भाइयो में तीसरे नंबर पर था।

फोटो: 4पीएम

खुले स्कूल

उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश में बाद 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल आज पूरे प्रदेशभर में खुल गए। राजधानी लखनऊ के गोमतीनगर स्थित सीएमएस स्कूल में लम्बी छुट्टी के बाद छात्र जब स्कूल पहुंचे तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा।

वोट की चोट के जरिए दें भाजपा को जवाब: योगेंद्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नोएडा। संयुक्त किसान मोर्चा के योगेंद्र यादव ने ग्रेटर नोएडा में किसानों से भारतीय जनता पार्टी को वोट की चोट देने की अपील की है। आरोप लगाए कि किसान आंदोलन की समाप्ति के लिए केंद्र सरकार ने लिखित में आश्वासन दिया था, लेकिन अब वादों से मुंह मोड़ लिया। उनका कहना है कि किसान मोर्चा किसी अन्य राजनीतिक दल को वोट देने की अपील नहीं कर रहा है, लेकिन किसानों के साथ भाजपा द्वारा किए गए वादा खिलाफी का जवाब अब वोट की चोट से दिया जाएगा। एक महीने तक का इंतजार किया गया, लेकिन केंद्र सरकार ने मांगें पूरी नहीं की।

फोटो: 4पीएम

बीजेपी में हुए शामिल

भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आज पूर्व सांसद रघुनाथ शाक्य सहित विभिन्न दलों के लोग उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्या और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत बाजपेई की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। भाजपा सरकार बनाने का संकल्प भी लिया।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक **बबिता चतुर्वेदी** के लिए **4पीएम** आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। **प्रधान संपादक**- अर्चना दयाल, **संपादक** - संजय शर्मा, **स्थानीय संपादक** - सूर्यकांत त्रिपाठी*, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website**: www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।